भास्कर ब्रेकिंग • पहली बार किसी राज्य का सरकारी ई-वॉलेट

सरकार गूगल-पे और फोन-पे जैसा जनाधार ई-वॉलेट लाएगी

अर्पित शर्मा | जयपुर

राज्य में सरकार पहली बार सरकारी ई-वॉलेट लाने वाली है। यह पेटीएम, फोन-पे, गूगल-पे की तरह हर जगह भुगतान करने, बिल जमा कराने, मनी ट्रांसफर, शॉपिंग से लेकर हर ट्रांजेक्शन में काम आएगा। सरकार ने 4.5 करोड़ रुपए खर्च कर इसे तैयार कराया है और ट्रायल पूरा हो चुका है।

सरकार 10 अगस्त से शुरू होने वाली इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के साथ ही जनाधार ई-वॉलेट लॉन्च करेगी। इसके लिए सरकार ने आरबीआई से लाइसेंस लिया है। प्रदेश में 1.99 करोड़ परिवारों के पास जनाधार है, सभी कार्ड धारक अपने मोबाइल से इस ई-वॉलेट का यूज कर सकेंगे। 10 अगस्त से हर जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाए जाएंगे।

10 से सरकार मोबाइल देने के लिए कैंप लगाएगी

राज्य सरकार 10 अगस्त से प्रदेश भर में मोबाइल बांटने के लिए कैंप लगाएगी। इसमें विधवा, नरेगा, शहरी रोजगार, कॉलेज - स्कूल छात्राओं को पहले मोबाइल दिया जाएगा। शुरुआत करीब 40 लाख महिलाओं से की जा रही है। कैंप में ही जनाधार ई वॉलेट की केवाईसी करके पैसा डाला जाएगा। साथ ही मौके पर ही कुछ कंपनियां अपने मोबाइल हैंडसेट दिखाएंगी। मोबाइल लेने के बाद डीओआईटी की एक टीम मोबाइल में ई मित्र सहित राज्य सरकार की कई एप भी मोबाइल में इंस्टॉल करेगी।

शुरुआत : मोबाइल और नेट रिचार्ज के ₹6800 ट्रांसफर होंगे

डीओआईटी के अधिकारियों ने बताया कि निजी एप के जरिए पैसा ट्रांसफर करते तो संबंधित कंपनी को कमीशन देना पड़ता। यह पहला ई-वॉलेट है जो जनाधार कार्ड से जुड़ा होगा। मोबाइल के लिए लगने वाले कैंप में केवायसी कर इसे शुरू कर दिया जाएगा। सरकार के पास बड़ा जनाधार डेटाबेस होने से यह सुरक्षित भी है। सबसे पहले इसमें मोबाइल व नेट के लिए 6,800 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।

मंशा: सब्सिडी, साइकिल-स्कूटी- का पैसा इसी में

सूत्रों के अनुसार सरकार की तैयारी है कि भविष्य में सभी तरह के डीबीटी जैसे गैस सब्सिडी, छात्राओं को स्कूटी-साइकिल वितरण जैसी योजनाओं का पैसा भी इसी ई-वॉलेट के जरिए लाभार्थी को दिया जाए। डीओआईटी के आयुक्त इंद्रजीत सिंह का कहना है कि डीओआईटी ने सॉफ्टवेयर और ई वॉलेट तैयार किया है। इसका बड़े स्तर पर ट्रायल किया है। इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकेंगे। भविष्य में लोगों को इससे सभी संबंधित सुविधाएं मिलेंगी।